IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों और अवसरों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

An Analytical Study on Challenges and Opportunities of NEP 2020

Dr. Aslam Sayeed[1] and Pratima Shukla[2]
Professor, Department of Commerce[1]
Research Scholar[2]
Amicable Knowledge Solution University, Satna, Madhya Pradesh, India[1]
Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, India[2]
proff.aslam@gmail.com

सारॉंशः

शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है इसलिए प्रत्येक देश अपनी परंपरा के अनुसार अलग–अलग शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक अच्छी तरह से सोची समझी और परिभाषित की गयी भविष्य की शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर नई शिक्षा नीति 2020 एक सुधार है । यह नीति व्यापक है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो रुपरेखा बनाई गयी है उसमे उच्च शिक्षा के साथ–साथ भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी स्थान दिया गया है

जैसा कि ऊपर ये बताया गया की NEP 2020, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किया गया एक सुधार है जिसके लिए जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी जिसने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरु किया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में एनईपी का मसौदा प्रस्तुत किया गया था नई शिक्षा नीति के इस मसौदे को लेकर पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर कई सार्वजनिक परामर्श किये बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक कठोर परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर नई शिक्षा नीति को जारी किया गया.

नीति का उद्देश्य यह है की 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए भरसक प्रयास किया जाये साथ ही नीति जारी होने के फौरन बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी भाषा विशेष का अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा साथ में ये भी कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

एनईपी में भाषा नीति की प्रकृति में व्यापक दिशानिर्देश दिए गए और यह कहा गया की यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर करता है कि वे इस नयी शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर स्वविवेक से निर्णय लें क्योकि भारत में शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है।

भारत में कर्नाटक मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है। ऐसी आशा की जा रही है नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 तक भारत के सभी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

प्रस्तावना .

किसी भी देश की प्रगति के साथ–साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (National Education Policy 2020) को मंजूरी दी गई। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2030–2032 तक भारत दस ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाएं भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संचालित नहीं की जा सकती इनको संचालित करने के लिए ज्ञान के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भारतीय शिक्षा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू करने का निर्णय लिया है

चौथे औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के लिए प्रधान मंत्री के हालिया आह्वान के अनुरूप भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गयी जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में तथा राष्ट्र की केंद्रित शिक्षा प्रणाली को एक समान और जीवंत ज्ञान में स्थायी रूप से बदलने में सीधे योगदान देती है

नयी शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख मुद्दे कुछ इस प्रकार से है

1. विभिन्न विषयों में छात्रों की प्रारंभिक स्ट्रीमिंग।
2. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के छात्रों का उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान सकल नामांकन अनुपात केवल 25% से 30% के मध्य ही रहा
3. छात्रों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा में नवाचार की कमी।
4. नवाचार करने के लिए पर्याप्त शिक्षक का न होना साथ ही और संस्थागत स्वायत्तता की कमी होना
5. अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचारों की कमी।
6. उच्च शिक्षा संस्थानों में शासन और नेतृत्व का उप–स्तर।
7. उत्कृष्ट एवं नवाचार स्थापित करने वाली संस्थानों को बाधित करते हुए नकली कॉलेजों को पनपने की अनुमति देने वाली एक भ्रष्ट नियामक प्रणाली

नई शिक्षा नीति 2020के महत्वपूर्ण उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।
2. नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये के आधार पर विभाजित किया गया है।
3. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

4. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास तथा 'भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language& ISL) को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
5. नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा ।
6. नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence& AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात कही गई है।
7. नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers& NPSTs) का विकास और चार वर्ष के एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम कीअवधारणा प्रस्तुत की गई है।
8. नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities& MERUs) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है

1. नई स्वीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली (एनईपी 2020) की नीतियों पर प्रकाश डालना और उनका अवलोकन करना।
2. भारत में वर्तमान में अपनाई गई नीति के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तुलना करना।
3. नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 में नवाचारों की पहचान करना।
4. भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी 2020 के प्रभाव की भविष्यवाणी करना।
5. एनईपी 2020 की उच्च शिक्षा नीतियों के गुणों पर चर्चा करना।
6. अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और सुधार के लिए सुझाव।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. NEP 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है ऐसे में इतने अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये बहुत से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।जो नीति के घोषित लक्ष्यों में से एक है, इसका मतलब यह होगा कि हमें अगले 15 साल के लिए हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय खोलना होगा हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय को निरंतर आधार पर खोलना निस्संदेह एक बड़ी चुनौती है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2 करोड़ बच्चों को स्कूल प्रणाली में वापस लाना है जो वर्तमान में स्कूलों में नहीं हैं। 15 वर्षों में इसे पूरा करने के लिए हर हफ्ते लगभग 50 स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल हैं।

4. इस नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, हालाँकि इन बदलावों को लागू करने के लिये संसाधनों (धन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति आदि) का प्रबंध एक बड़ी चुनौती होगी।
5. वर्तमान में शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामले में देश के अलग–अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर है, गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index) में देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया है, ऐसे में छात्रों के लिये इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन होगा।
6. उच्च शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतर–अनुशासनात्मक शिक्षा पर ध्यान देना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।
7. पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो वर्ष 1968 में जारी की गई जिसके अंतर्गत शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अगली सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया परंतु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो सरकार की नीतिगत असफलता और कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
8. कोविड –19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच राज्यों के लिये इन सुधारों को लागू करने के लिये आवश्यक धन एकत्र करना बहुत ही कठिन होगा।
9. वर्तमान में देश के 70% उच्च शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के हैं और 70% से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिये निजी संस्थानों में प्रवेश करते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहुँच के विस्तार में निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है।
10. निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन की वित्तीय चुनौतियों और छात्रों के समक्ष आने वाली शुल्क संबंधी चुनौतियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।

यह परिषद संभावित दाताओं को तीन बंदोबस्ती निधियों (उच्च शिक्षा अवसंरचना, छात्रवृत्ति और शोध अनुदान से संबंधित) की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली में मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है।

निष्कर्ष

हर देश में अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, प्रौद्योगिकी अपनाने और स्वस्थ मानव व्यवहार को तय करने में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है।

उच्च शिक्षा के प्रसाद में देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए जीईआर में सुधार देश की सरकार के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधारकरनेके लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के साथ–साथ हर उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उच्च शिक्षा प्रणाली खुद को एक अनुशासन के भीतर और सभी विषयों में मूलविषयों और संबद्ध विषयों को चुनने की स्वतंत्रता के साथ छात्र केंद्रित के रूप में बदल देगी। संकाय सदस्यों को दिए गए नीतिगतढांचे

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

के भीतर पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन मॉडल चुनने की स्वायत्तता भी मिलती है। ये परिवर्तन शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से शुरू होंगे और वर्ष 2030 तक जारी रहेंगे जहांपहला स्तरका परिवर्तन बहुत अधिक दिखाई देने की उम्मीद है।

सरकार के लिये किसी भी नीति के कार्यान्वयन में सफलता हेतु प्रोत्साहन, साधन, सूचना, अनुकूलनशीलता, विश्वसनीयता और प्रबंधन जैसे तत्त्वों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है।

NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिये सरकार को पारदर्शी कार्यप्रणाली और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ानी होगी तथा प्रबंधन के प्रभावी सिद्धांतों को विकसित करना होगा। साथ ही सरकार को कानूनी, नीतिगत, नियामकीय और संस्थागत सुधारों को अपनाने के साथ एक विश्वसनीय सूचना तंत्र का निर्माण और नियामक संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अनुकूलनशीलता के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
   https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English.pdf
2. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019,
   https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf
3. योजना पत्रिका
4. अन्य पेपर लेख